



पी.एम. मोदी के मैसेज के कायल जोमैटो एजेंट हुए स्विस राष्ट्रपति, जमकर की तारीफ पर हमला

नई दिल्ली, प्रेसमैन भारत: 'यह युद्ध का युग नहीं, शांति का है', रूस-यूक्रेन और दुनियाभर में जारी अन्य युद्धों को लेकर पीएम मोदी के इस मैसेज को लेकर स्विस राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने जमकर तारीफ की है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाइ परमेलिन के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि यूक्रेन संकट को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है। भारत इस युद्ध के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति की समर्थन करता है। भारत के इसी रुख को लेकर स्विस राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी देते हुए सिबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों नेताओं ने दुनिया में जारी संघर्षों की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, 'जहां तक यूक्रेन की स्थिति का सवाल है, हम कूटनीतिक समाधान के पक्ष में हैं। हम इस मामले का कूटनीतिक समाधान खोजने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना करते हैं।'



'युद्ध खत्म होना चाहिए' वाले पीएम मोदी के मैसेज की तारीफ

उन्होंने कहा, 'मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्विस राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के रुख, विशेष रूप से उनके 'यह युद्ध का युग नहीं है, बल्कि शांति का युग है' मैसेज की जमकर तारीफ की है। साथ ही युद्ध को समाप्त करने के उनके हालिया रुख की भी बहुत सराहना की।'

यूक्रेन युद्ध पर भारत का लगातार जोर

भारत लंबे समय से यूक्रेन संकट के समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि युद्ध के बजाय बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकाला जाना चाहिए।

स्विट्जरलैंड ने भी अपनी पारंपरिक तटस्थता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए मंच उपलब्ध कराने की कोशिश की है। दावोस में जनवरी 2024 की बैठकों से लेकर जून 2024 में बर्गेनस्टॉक शिखर सम्मेलन तक स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन संकट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की।

UN सुधार और जिनेवा की भूमिका पर भी चर्चा

इससे पहले स्विस राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यूक्रेन युद्ध के अलावा संयुक्त राष्ट्र में सुधार और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। गाइ परमेलिन ने कहा कि मौजूदा समय अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और बढ़ते वैश्विक विभाजन के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर समानताएं हैं और दोनों देशों को नागरिक समाज, अकादमिक जगत तथा मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों, खासकर यूक्रेन युद्ध पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। स्विस राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रही है और ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समाधान तलाशने की जरूरत है, जिनसे सभी पक्षों को लाभ हो।

हैदराबाद: एक कपल ने डिलीवरी एजेंट के साथ मारपीट की। क्योंकि फूड डिलीवरी में देरी हो गई थी। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट के कारखाना पुलिस स्टेशन के इलाके में वासावी नगर में यह घटना हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सिकंदराबाद के वासवी नगर में फूड ऑर्डर में देरी को लेकर हुए झगड़े के बाद एक कपल ने जोमैटो के डिलीवरी एजेंट के साथ मारपीट की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज ऑनलाइन सामने आया है। यह घटना कारखाना पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। डिलीवरी एजेंट की पहचान आशीष के

तौर पर हुई है। फूड डिलीवरी में देरी के बाद कस्टमर के पते पर पहुंचा था। जोमैटो के डिलीवरी एजेंट आशीष एक कस्टमर के ऑर्डर किए गए फूड पार्सल को डिलीवर करने के लिए ऐप पर दिखाई गई लोकेशन पर गए। जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं। हालांकि कस्टमर ने ऐप में लोकेशन गलत डाली थी, इसलिए सही पता खोजने की कोशिश में आशीष को कुछ मिनटों की देरी हो गई। खबरों के मुताबिक, देरी की वजह से आशीष और ग्राहकों के बीच तीखी बहस हुई। शिकायत के अनुसार, बहस बढ़ गई और इसके बाद उस कपल ने डिलीवरी एजेंट के साथ मारपीट की।



अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे अमित शाह

तेलंगाना में 4 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल

हैदराबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चार अक्टूबर को तेलंगाना के दौरे पर आएंगे और मेडक जिले में साबर डेयरी परियोजना की आधारशिला रखेंगे तथा राज्य में अमूल द्वारा स्थापित पहले आधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह करीमनगर स्थित मेडिकल कॉलेज प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि डेयरी परियोजनाओं की स्थापना से तेलंगाना में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

तेलंगाना को लाभ होगा

उन्होंने कहा कि हाल में पारित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 से केवल पंजीकृत सहकारी समितियों के बजाय सहकारी क्षेत्र की किसी भी इकाई को वित्त पोषण मिल सकेगा, जिससे तेलंगाना को लाभ होगा। किशन रेड्डी के अनुसार, राज्य में करीब 50,000 सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनके एक करोड़ सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत सहकारी क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में

मदद करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने एक अक्टूबर को शाह के करीमनगर दौरे की तैयारियों का जायजा लिया।

तेलंगाना के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए

रेड्डी ने कहा कि राजग सरकार के पिछले 12 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने तेलंगाना के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि एनसीडीसी ने 2025-26 के खरीफ और रबी सत्र में धान खरीद के लिए 37,000 करोड़ रुपये जारी किए, जबकि 2026-27 के रबी सत्र के लिए 22,700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अकेले धान खरीद के लिए निगम ने 60,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।



'बीजेपी का मकसद मुसलमानों को हटाना'

ओवैसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर का मकसद नाम हटाना, नागरिकता पर सवाल उठाना और फिर जब कल एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) लागू हो तो लोगों को कतारों में खड़ा करवाना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनआरसी लागू की जाएगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े सुनील आंबेकर ने इसका समर्थन किया है।

बीजेपी ने ओवैसी को दिया जवाब

ओवैसी ने इन आरोपों को खारिज किया कि एआईएमआईएम फर्जी वोटों के दम पर चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्यार के दम पर चुनाव जीतती है। ओवैसी के इन आरोपों का जवाब देते हुए कि भाजपा और संघ परिवार के कार्यकर्ता असली मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भर रहे हैं, तेलंगाना भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एन.वी. सुभाष ने कहा कि कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप सिर्फ सार्वजनिक बयानों से साबित नहीं किए जा सकते।

'ओवैसी के पास सबूत हो तो दें'

सुभाष ने कहा कि अगर ओवैसी के पास चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के ठोस सबूत हैं, तो उन्हें उचित न्यायिक मंच पर जाने से कौन रोक रहा है? वह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाकर क्यों रुक जाते हैं? उन्हें सक्षम अधिकारियों के सामने सबूत पेश करने चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज की जांच की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बिना सबूत के चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर बार-बार सवाल उठाना बिल्कुल अलग बात है।

ओवैसी ने दे डाली बड़ी धमकी

मुसलमानों का नाम हटाने के लिए लाया गया फॉर्म-7

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर पर सवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता 'फॉर्म-7' जमा करके मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनसीडीसी ने 2025-26 के खरीफ और रबी सत्र में धान खरीद के लिए 37,000 करोड़ रुपये जारी किए, जबकि 2026-27 के रबी सत्र के लिए 22,700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अकेले धान खरीद के लिए निगम ने 60,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सुभाष ने कहा कि हैदराबाद में मतदाता सूची से जुड़े आरोपों-जिनमें एआईएमआईएम के पारंपरिक गढ़ से जुड़े आरोप भी शामिल हैं-की भी उसी तरह जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी के पास सबूत हैं, तो उन्हें पेश करना चाहिए। अगर उन्हें कोई शिकायत है, तो उन्हें कानून के तहत उपलब्ध विकल्प का सहारा लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी सबूत की जगह नहीं ले सकती और सिर्फ बार-बार दोहराने से आरोपों को चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर बार-बार सवाल उठाना बिल्कुल अलग बात है।

कि निर्वाचन आयोग और तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रिंटेड फॉर्म-7 जमा करके मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिशों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म-7 जमा करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा रहा है। **हर एक फॉर्म-7 की जांच हो** फॉर्म-7 एक मतदाता आवेदन फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार के लोग फॉर्म-7 जमा करके नाम हटवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को हर 'फॉर्म-7' की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए आवेदन कौन जमा कर रहा है।

'निर्वाचन आयोग करे कार्रवाई'

ओवैसी ने आरोप लगाया कि हैदराबाद के मुश्रीराबाद में भाजपा के एक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा किया था। उन्होंने कहा कि अगर गलत फॉर्म-7 जमा किए जाते हैं, तो निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए।

ओवैसी ने दी सीधी धमकी

ओवैसी ने कहा कि अगर यह ड्रामा बंद नहीं हुआ, तो याद रखिए, हम हैदराबाद की सड़कों

पर वह 'मंत्र' पढ़ेंगे, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर नहीं पढ़ा गया था। तब उन्हें बड़ी मुश्किल होगी। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि फॉर्म-7 के जरिये वास्तविक मतदाताओं के नाम सिर्फ इसलिए हटवा दिए जाएं, क्योंकि वे मुसलमान हैं। उन्होंने एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं से अधिकारियों से यह पूछने के लिए कहा कि 'फॉर्म-7' किसने जमा किए।

'6 बच्चे समस्या क्यों?'

ओवैसी ने चेतावनी दी कि हैदराबाद में दिल्ली और मुंबई में हुए विरोध-प्रदर्शनों से दोगुना या तीन गुना बड़े विरोध-प्रदर्शन होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि एसआईआर एक गलत प्रक्रिया है। हालांकि, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। ओवैसी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के छह बच्चे हैं, तो इससे समस्या क्यों होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके खुद के छह बच्चे हैं।



प्रकाश राज की ब्रीफिंग में तेलंगाना भाजपा का हंगामा

हैदराबाद: सोमाजीगुडा प्रेस क्लब में एक्टर से नेता बने प्रकाश राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रकाश राज ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) पर मीडिया ब्रीफिंग की थी और मांग की कि SIR को रद्द किया जाए और पुरानी वोटर लिस्ट को बहाल किया जाए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चलने पर, बीजेपी के राज्य 'ऑल सेल्स कोऑर्डिनेटर' अमरनाथ सारंगुला के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता प्रेस क्लब पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डालने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने ऐसे प्लेकार्ड दिखाए जिन पर लिखा था कि 'वह वोट चोर हैं जिन्होंने चार जगहों पर वोट डाला है' और प्रकाश राज के खिलाफ नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए अमरनाथ ने कहा कि चार राज्यों में वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना एक आपराधिक अपराध है। फिर भी वह मोदी सरकार और बीजेपी की आलोचना करते हैं।

ज्ञानेश कुमार के विसर्जन की कही बात

प्रकाश राज ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आलोचना करते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी के उत्सव के तहत गणेश प्रतिमाओं का 'विसर्जन' हो चुका है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का 'विसर्जन' होना बाकी है। मीडिया में आई उन खबरों का हवाला देते हुए कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं द्वारा नाम शामिल किए जाने के लिए दायर 38 लाख अपीलें न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। इनके निपटारे में 10-12 साल लग सकते हैं, उन्होंने सवाल किया कि क्या इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों को इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूरे देश में गणेश विसर्जन हो चुका है। अब ज्ञानेश कुमार के विसर्जन की बारी है।



बीएलओ पर लगाए आरोप

प्रकाश राज ने कहा कि उन्होंने विभिन्न जिलों का 10-दिवसीय दौरा कर लोगों से मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि केवल इसलिए उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए क्योंकि जब बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उनके घर पहुंचे, तब वे घर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि काम के सिलसिले में दूसरे स्थानों पर गए दिहाड़ी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

तेलंगाना बीजेपी ने की आलोचना

उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या 'मन की बात' करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले से ही एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाया था। प्रकाश राज ने कहा कि हमारी मांग है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसे पूरी तरह रद्द किया जाए। इस बीच, भाजपा की तेलंगाना इकाई के मुख्य प्रवक्ता एन. वी. सुभाष ने सीईसी के खिलाफ की गई प्रकाश राज की अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की।

सुभाष ने एक बयान में कहा कि प्रकाश राज को निर्वाचन आयोग की आलोचना करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की तुलना प्रतिमा विसर्जन से करना राजनीतिक आलोचना की सीमा से आगे बढ़कर एक संवैधानिक संस्था के प्रति अनादर है। लोकतंत्र में उपहास नहीं, बल्कि सार्थक बहस की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश राज को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है, तो उन्हें 'भड़काऊ बयानबाजी' करने के बजाय उचित मंच के समक्ष तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए।

राहुल-अखिलेश समेत विपक्ष के बड़े सांसद होंगे मार्च में शामिल

नई दिल्ली: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष का आंदोलन आज दिल्ली में सड़क पर उतरेगा। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे।

मार्च में शामिल होंगे कांग्रेस के बड़े नेता

मार्च में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, प्रियंका गांधी वाड़ा समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता और सांसद शामिल होंगे। आज सुबह सभी सांसद साढ़े 10 बजे संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्र होंगे और फिर 11 बजे वहां से मार्च शुरू करेंगे।

मामले में क्या है विपक्षी दलों का कहना

इंडि गठबंधन ने 30 सितंबर को हुई बैठक में 6 अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च का फैसला किया था। इसके तहत संसद भवन परिसर से सांसद एक साथ चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर रवाना होंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि यह मार्च चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर उनकी चिंताओं को चुनाव आयोग के सामने रखने के लिए किया जा रहा है।

मार्च में शामिल नहीं होगी आप

हालांकि, इंडिया गठबंधन के सभी दलों की भागीदारी को

लेकर स्थिति में बदलाव आया है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह 6 अक्टूबर के इंडि गठबंधन के मार्च में शामिल नहीं होगी। पार्टी इस मुद्दे पर अपने स्तर पर आंदोलन कर रही है। AAP और DMK ने 30 सितंबर की इंडिया गठबंधन बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था।

चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

इसके बावजूद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के मार्च में शामिल होने की तैयारी है। मार्च ऐसे समय हो रहा है जब विपक्ष चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि आयोग ने SIR से जुड़ी प्रक्रिया में अनियमितताओं के विपक्षी आरोपों को खारिज किया है।



HYDRAA प्रजावाणी को 61 शिकायतें

हैदराबाद: झीलों को कब्जे से बचाने और उन्हें पूरी तरह से विकसित करने का तरीका एक मिसाल बन गया है। HYDRA के दखल से पहले और बाद की झीलों की हालत में बड़ा बदलाव साफ़ दिखता है; बदबू गायब हो गई है और माहौल खुशनुमा हो गया है। चूंकि HYDRA का काम अभी तक कुछ खास झीलों तक ही सीमित रहा है, इसलिए सोमवार को एजेंसी के जन-शिकायत सत्र के दौरान कई लोगों ने मांग की कि उनके इलाकों की झीलों का भी विकास किया जाए। विकास की इस प्रक्रिया—जिसमें सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के अलावा गाद निकालना (10 फीट से ज्यादा जमा गाद हटाना) और बदबू खत्म करना भी शामिल है—को लोगों ने खूब सराहा है। जन-शिकायतें सुनने वाली संस्था 'जनवानी' ने HYDRA से शहर की सभी झीलों में यह विकास कार्य करने का आग्रह किया और उन खास झीलों की जानकारी

देते हुए एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सुधारी गई झीलों में सीवेज का पानी जाने से रोकने के उपाय करने का भी अनुरोध किया और सुझाव दिया कि उनमें सिर्फ बारिश का पानी (मानसून के दौरान) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से साफ़ किया गया पानी ही डाला जाए। इसके अलावा, उन्होंने गांधीपेट झील और हिमायत सागर को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के बारे में भी ज्ञापन सौंपे और अधिकारियों से इन दोनों जलाशयों को बचाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। सोमवार को HYDRAA के 'प्रजावानी' (जन-शिकायत निवारण) सत्र के दौरान कुल 61 शिकायतें मिलीं, जिनकी समीक्षा HYDRAA कमिश्नर AV रंगनाथ ने की। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान की ज़िम्मेदारी सौंप दी।

CISF जवान पर धारदार हथियार से हमला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक जवान पर कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद नई दिल्ली जिला पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है, साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमला किन परिस्थितियों में किया गया। सोमवार को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही घायल जवान का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेडिकल जांच कराई गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया

घटना को लेकर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रदर्शन के दौरान विवाद किस बात को लेकर हुआ और हमले के पीछे कौन लोग शामिल थे। दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं, एसआईआर और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर विभिन्न शहरों में जारी व्यापक आंदोलन किए गए थे। जिसमें आईसा, आम आदमी पार्टी समेत कई संगठनों ने भाग लिया था। दिल्ली में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।



पुलिस ने 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था

इससे पहले, शुक्रवार को मध्य दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्र कार्यकर्ताओं और नेताओं समेत 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। रविवार को आइसा कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में लगाए गए अवरोधकों व भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे जंतर-मंतर की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारी अशोक रोड स्थित आंध्र भवन सर्कल से जंतर-मंतर की ओर मार्च करते हुए नारे लगा रहे थे और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच निर्धारित प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को अवरोधक पार करने से रोकने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई।

क्या अवैध शेड को हरी झंडी मिल गई है..?

कुतुबुल्लापुर: साइबरबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुथबुल्लापुर ज़ोन के गजुलारामाराम सर्कल (सर्कल-57) में, बेईमान लोग बिना मंजूरी के बहुमंजिला इमारतें और कमर्शियल शेड बना रहे हैं। TG-bPASS नियमों का उल्लंघन करके, ये अवैध बिल्डर सरकारी खजाने को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। गजुलारामाराम सर्कल की कई कॉलोनियों और इलाकों में ऐसी कई इमारतें बिना किसी मंजूरी के बनाई जा रही हैं।



निर्माण कार्य बिना रुके चल रहा है, फिर भी स्थानीय टाउन प्लानिंग अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। कई न्यूज़ रिपोर्ट और स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद, ये भ्रष्ट अधिकारी समस्याओं को नज़रअंदाज़ करते हैं और अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं। हाल ही में, मधापुर के अंजैया नगर में 60 वर्ग गज के प्लॉट पर बन रही एक इमारत से जुड़ी घटना के बाद, कुछ अवैध ढांचों को आंशिक रूप से तोड़ा गया। हालांकि वहां कई बहुमंजिला इमारतें और कमर्शियल शेड हैं, लेकिन स्थानीय म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर ने केवल कुछ स्लैब में छेद किए और कुछ शेड को आंशिक रूप से तोड़ा—असल में आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए सिर्फ़ दिखावा किया—और फिर चले गए। इसी तरह, महादेवपुरम कॉलोनी में U-90 (UPEL प्राइवेट लिमिटेड) के बगल वाले प्लॉट पर बने शेड के बिल्डर ने तोड़फोड़ के बाद कुछ दिनों तक ढांचे को वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन लगभग दो हफ्ते बाद फिर से काम शुरू कर दिया। स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं: क्या मीडिया कवरेज और शिकायतों के बावजूद मरम्मत का काम फिर से शुरू होने का मतलब स्थानीय टाउन प्लानिंग विभाग और म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर से "हरी झंडी" मिलना है? डिप्टी कमिश्नर, जिन्होंने शुरुआती तोड़फोड़ की देखरेख की थी, उन्हें इस स्थिति के बारे में सफ़ाई देनी चाहिए।



अनिशा के जाल में ‘चार लाख की छेल’

क्या तेलंगाना में डायनासोर घूमते थे?

तेलंगाना ACB के इतिहास में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। मेहदीपट्टनम में GHMC टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र सुनीता को कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए ₹4 लाख की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ACB अधिकारियों ने एक सुनियोजित छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि अगर सरकारी दफ़्तरों में रिश्त मांगी जाए, तो वे ACB से संपर्क करें।

हैदराबाद: एंटी-कorrप्शन ब्यूरो (ACB) के अधिकारियों ने मेहदीपट्टनम GHMC ऑफिस में अचानक छापे मारा। इस कार्रवाई के दौरान, टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र सुनीता को ₹4 लाख की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन पर कंस्ट्रक्शन परमिट और मंजूरी के लिए रिश्त मांगने का आरोप था। इस जानकारी के आधार पर, ACB अधिकारियों ने एक योजना बनाई और उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। बताया जा रहा है कि सुनीता ने एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के परमिट के लिए कुल ₹8 लाख की रिश्त मांगी थी; ACB अधिकारियों ने उन्हें ₹4 लाख की पहली किश्त लेते हुए हिरासत में ले लिया।



अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने रिश्त की रकम ज़ब्त कर ली है। सुनीता को हिरासत में लेने के बाद, ACB अधिकारियों ने मेहदीपट्टनम GHMC ऑफ़िस में तलाशी ली। उन्होंने ज़रूरी फ़ाइलों, दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड की जाँच की और अहम दस्तावेज़ ज़ब्त किए। ऐसा लगता है कि अधिकारी अभी रिश्त की माँग के बारे में और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मामले की पूरी जानकारी और आगे की कानूनी कार्रवाई के बारे में ACB के आधिकारिक बयान का इंतज़ार है। अधिकारी लोगों को सलाह देते हैं कि अगर कोई सरकारी ऑफ़िस में सरकारी काम के लिए रिश्त माँगे, तो वे ACB से संपर्क करें। रिश्त के आरोपों पर अंतिम फ़ैसला जाँच और कानूनी कार्रवाई के बाद लिया जाएगा।

जितिया व्रत के दिन ही मां ने ‘खोया बेटा’

नई दिल्ली: ऊट्टी से घर लौट रहे एक युवक पर शाहबाद डेयरी थाना इलाके में चाकू ताबड़तोड़ हमला किया गया। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सचिन उर्फ काला के रूप में हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर मुख्य आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। दो अन्य को हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, सचिन दूसरे समुदाय की एक लड़की से बातचीत करते थे। इसको लेकर लड़की के परिवार के साथ उनका विवाद चल रहा था। पहले इस विवाद को सुलझा लिया गया था, लेकिन शनिवार रात आरोपियों ने मौका देखकर सचिन पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही शाहबाद डेयरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मौके पर फॉरेंसिक और क्राइम टीम भी पहुंची और घटनास्थल से ज़रूरी सबूत जुटाए।

जितिया के व्रत वाले दिन मां ने खोया बेटा

मृतक की मां ने बताया कि जितिया पर्व के दिन उन्होंने सचिन के लिए व्रत रखा था और उसी रात बेटे को खो दिया। पिता सुरेंद्र ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चाचा चंद्रिका ने बताया कि ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं था, जिस कारण भतीजे की हत्या कर दी गई। शनिवार रात सचिन से बात हुई थी। उसने कहा था कि थोड़ी देर में घर आ रहा हूं। मैंने कहा कि साथ में खाना खाएंगे, लेकिन वह नहीं लौटा। पुलिस ने सचिन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कॉमन गर्लफ्रेंड को लेकर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार कॉमन गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद हुआ था। जिस लड़की से दोस्ती सचिन की थी उसी से अमन की भी थी। पुलिस ने अमन उर्फ आरिफ खान और उसकी मां नफीसा और मामा मोहम्मद इमरान को पकड़ लिया है।



पुलिस इंस्पेक्टर एन. सुरेश ने दी बधाई

साइबराबाद: जगदगिरीगुट्टा पुलिस स्टेशन की महिला पुलिस कॉन्स्टेबल तेजश्री ने 2026 तेलंगाना राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता (बैडमिंटन) में सिंगल्स और डबल्स दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल और मिक्सड डबल्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। जगदगिरीगुट्टा के इंस्पेक्टर एन. सुरेश ने उनके शानदार प्रदर्शन और मेडल जीतने की उपलब्धि के लिए उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। इसके बाद, इंस्पेक्टर एन. सुरेश ने हेड कॉन्स्टेबल कट्टावीरा नागा अंजी बाबू की बेटी हेमा हसिनी को भी शॉल देकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी, क्योंकि उन्होंने महबूबनगर के SVS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में BDS कोर्स में सीट हासिल की थी।



कर्नाटक में जेलों के DIG, सोमशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। परप्पना अग्रहारा जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करते हुए, उनका शंकर नाम के एक कैदी की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था; इस अफेयर को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने नकली कागज़ात का इस्तेमाल करके शंकर की रिहाई का इंतज़ाम किया। उन्होंने पहले कैदी की पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फँसाया और फिर सुप्रीम कोर्ट के नकली आदेश बनाकर इस घिनौने काम को अंजाम दिया। उन्होंने उम्रकैद की सज़ा काट रहे शंकर के नाम से सुप्रीम कोर्ट का एक नकली आदेश तैयार किया और उसी के आधार पर उसकी रिहाई करवा ली। हालाँकि कर्नाटक में इस तरह की कई चौकाने वाली घटनाएँ सामने आई हैं, लेकिन इस मामले ने काफ़ी सनसनी फैला दी। जाँच के दौरान उन्होंने कानून से बचने की कोशिश की; लेकिन कैदी की पत्नी के साथ अवैध संबंध और उसके बाद कैदी की रिहाई कराने की साज़िश के सबूत मिलने के बाद कर्नाटक सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

क्या तेलंगाना में डायनासोर घूमते थे?

- वेमनापल्ली इलाके में डायनासोर के अवशेष मिले
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये अवशेष 1984 में मिले थे
- प्राणहिता नदी बेसिन में जीवाश्मों के निशान मिले
- राजाराम में काकतीय काल की मूर्तियाँ मिलीं
- 12वीं सदी की दशावतार मूर्तियां

खास खबर: तेलंगाना का नाम सुनते ही ऐतिहासिक किले, मंदिर और घने हरे-भरे जंगल याद आते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि करोड़ों साल पहले इस ज़मीन पर डायनासोर घूमते थे? मंचरियल ज़िले का वेमानापल्ली इलाका ऐसे ही दिलचस्प राज़ समेटे हुए है। स्थानीय लोगों के अनुसार, प्राणहिता नदी के बेसिन में डायनासोर के अवशेष और कई प्राचीन जीवों के जीवाश्म मिले हैं। खास बात यह है कि इस इलाके में काकतीय काल की ऐतिहासिक निशानियाँ भी मौजूद हैं।

डायनासोर के अवशेष

वेमानापल्ली, महाराष्ट्र की सीमा के पास प्राणहिता नदी के किनारे बसा है। 1984 में, भू-विज्ञान और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मंगेनापल्ली वन क्षेत्र में डायनासोर के अवशेषों की पहचान की थी। लगभग 14 मीटर लंबे और 5.5 मीटर ऊंचे जीव के अवशेष मिलने से उस समय काफी हलचल मच गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सम्पुटम, ओड्डुगुडेम और मंगेनापल्ली इलाकों में भी अवशेष मिले हैं।



पुणे बंद, 100000 छात्रों संग मुंबई मार्च

राहुल गांधी भी आएंगे, MPSC केस में रोहित पवार का 48 घंटे का अल्टिमेटम

मुंबई: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को छठवें दिन भी जारी है। इस बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को 48 घंटे का कड़ा अल्टिमेटम दिया है कि वह छात्रों की मांगों को पूरा करे। इन मांगों में हाल ही में हुए पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी के कारण एमपीएससी के चेरमैन विवेक भीमन्वार को तुरंत पद से हटाना भी शामिल है। रोहित पवार ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो 1,00,000 से अधिक छात्र पुणे की सड़कों पर उतर आएंगे। प्रदर्शनकारी या तो पूरी तरह से पुणे बंद करवाएंगे या फिर सीधे मुंबई में मंत्रालय तक एक बड़ा मार्च निकालेंगे।

राहुल गांधी पहुंचेंगे पुणे

विरोध प्रदर्शन के पहले दिन से ही उम्मीदवारों के साथ मौजूद रोहित पवार ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 7 या 8 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों से मिलने की उम्मीद है। उस समय पुणे की सड़कों पर हजारों उम्मीदवारों की भारी भीड़ अपनी ताकत दिखाएगी।

मुंबई में मंत्रालय तक मार्च

रोहित पवार ने कहा कि सीजेपी के अभिजीत दिपके की अपील के बाद पुणे शहर ठप हो सकता है। अब एमपीएससी के उम्मीदवार और उनके माता-पिता ही फैसला करेंगे। उस समय पुणे के निवासियों को इन छात्रों का समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी के 7 या 8 अक्टूबर को आने की संभावना है। हमारा अनुमान है कि उस दिन पुणे की सड़कों पर लगभग 1,00,000 छात्र होंगे। ये छात्र या तो पुणे बंद का आह्वान करेंगे या सीधे मुंबई में मंत्रालय तक मार्च करेंगे। हम सरकार को दो दिन का अल्टिमेटम दे रहे हैं।

पत्थर में छिपा जीवन

स्थानीय लोगों का कहना है कि वेमनापल्ली के आस-पास पेड़-पौधों के जीवाश्म (फॉसिल) पाए जाते हैं। यहाँ की नदियों और धाराओं के किनारों पर अलग-अलग आकार की चट्टानें मिलती हैं; इनमें से कुछ मछली, स्टार्फिश और कुछ जैसी दिखती हैं। माना जाता है कि भारी बारिश और बाढ़ के दौरान पेड़ रेत की परतों के नीचे दब गए थे और लंबे समय में जीवाश्म में बदल गए।

काकतीय वंश के निशान भी...

वेमनापल्ली का महत्व सिर्फ डायनासोर तक ही सीमित नहीं है। राजाराम गाँव में मौजूद *दशावतार* (भगवान विष्णु के दस अवतार) की मूर्तियाँ लगभग 12वीं सदी की मानी जाती हैं। इन्हें काकतीय काल की ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। इस तरह, यह इलाका एक अनोखा संगम पेश करता है: यहाँ लाखों साल पहले मौजूद जीवों के निशान और सदियों पहले इंसानों द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक निशानियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं।

प्रकृति और इतिहास का संगम

प्राणहिता नदी, घने जंगलों, दुर्लभ पौधों की प्रजातियों, जीवाश्मों, डायनासोर के अवशेषों और काकतीय काल की मूर्तियों के साथ, वेमनापल्ली प्रकृति, इतिहास और भू-वैज्ञानिक रहस्यों को एक ही जगह पर समेटे हुए है। इस इलाके की प्राचीन धरोहरों पर और वैज्ञानिक शोध से तेलंगाना के अतीत के बारे में कई दिलचस्प बातें सामने आ सकती हैं।



पुणे बंद, 100000 छात्रों संग मुंबई मार्च

पुणे में छात्रों के आंदोलन की मुख्य वजह क्या
रोहित पवार ने कहा कि इस आंदोलन की मुख्य वजह परीक्षा बोर्ड में फैला व्यवस्थित भ्रष्टाचार है। उन्होंने एमपीएससी के चेरमैन विवेक भीमन्वार के तुरंत इस्तीफे की मांग की और कमीशन की भर्ती प्रक्रियाओं की पूरी तरह से ऑडिट और सफाई करने की बात कही।

नितेश राणे ने साधा निशाना

वहीं, भाजपा नेता और राज्य मंत्री नितेश राणे ने रोहित पवार से अपील की कि वे राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों को बंधक न बनाएं। उन्होंने कहा कि यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और दोनों नेताओं को मिलकर रचनात्मक रूप से काम करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भविष्य में रोहित पवार उनके साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर बैठ सकते हैं। रोहित पवार को भी बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वे छात्रों के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। उन्हें विरोध करना चाहिए लेकिन छात्रों को बंधक नहीं बनाना चाहिए।

‘विरोध करें, पर छात्रों को बंधक न बनाएं’

मंत्री राणे ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। हम छात्रों के भले के लिए मंत्रालय में बैठते हैं। रोहित पवार मेरे दोस्त हैं। कल, वे सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। वे अच्छे कामों की तारीफ करने वाले व्यक्ति हैं। हम छात्रों के लिए मिलकर काम करेंगे। वे विरोध जारी रख सकते हैं लेकिन उन्हें छात्रों को बंधक नहीं बनाना चाहिए।



आईपीएस प्रीता वर्मा को अतिरिक्त प्रभार

पटना: बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक संभालती रहेंगी। सम्राट सरकार के गृह विभाग ने अगले आदेश तक बिहार की कार्यवाहक DGP प्रीता वर्मा को एक्सटेंशन दे दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1991-बैच की बिहार कैडर की IPS अधिकारी प्रीता वर्मा के पास अभी जो अतिरिक्त प्रभार है, वह अगले आदेश तक जारी रहेगा।

विनय कुमार के छुट्टी पर जाने पर IPS प्रीता वर्मा को मिली थी जिम्मेदारी

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, प्रीता वर्मा को 15 सितंबर को जारी विभागीय आदेश के ज़रिए बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। उन्होंने विनय कुमार की जगह ली थी, जो बिहार DGP के पद पर रहते हुए 21 दिन की छुट्टी पर चले गए थे। विनय कुमार को एक हफ्ते पहले बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त(CIC) नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने बिहार डीजीपी के पद से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली थी।

अभी किस पद पर काम कर रही हैं प्रीता वर्मा?

प्रीता वर्मा अभी बिहार होम गार्ड्स और फायर सर्विसेज़ की डायरेक्टर जनरल-सह-कमांडेंट जनरल के तौर पर काम कर रही हैं। डीजीपी का अतिरिक्त



प्रभार मिलने के बाद से वह अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के कामकाज की देखरेख भी कर रही हैं। बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रीता वर्मा अगले आदेश तक बिहार DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालती रहेंगी। यानी जब तक बिहार में डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक प्रीता वर्मा DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी।

कौन हैं आईपीएस प्रीता वर्मा?

बिहार कैडर की 1991-बैच की IPS अधिकारी प्रीता वर्मा, राज्य कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। मूल रूप से राजस्थान की प्रीता वर्मा की शैक्षणिक योग्यता बी.ए. है। तीन दशक से अधिक लंबे पुलिस करियर में वह बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, सहरसा और सीवान जैसे जिलों की पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं। आईपीएस प्रीता वर्मा को पुलिस में सराहनीय सेवा के लिए 2009 में पुलिस पदक भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (2023) भी मिला है।

उत्तराखंड कांग्रेस में अकेले अभियान पर रोक

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान के बीच पार्टी हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनावी अभियान पार्टी संगठन के तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चलाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हरीश रावत से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में सभी नेताओं को साथ लेकर कांग्रेस के बैनर तले सामूहिक अभियान चलाया जाएगा। **व्यक्तिगत अभियान की अनुमति नहीं** केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से राज्य में चल रहे चुनावी अभियानों को लेकर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के सभी अभियान उत्तराखंड के नेताओं के साथ मिलकर, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ाए जाएंगे। अभियान का एकमात्र लक्ष्य पार्टी की जीत सुनिश्चित करना होगा।

केसी वेणुगोपाल ने यह भी साफ किया कि पार्टी की ओर से व्यक्तिगत अभियान की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में केवल पार्टी संगठन की ओर से तय सामूहिक कार्यक्रम ही आयोजित किए जाएंगे।

उठ रहे थे सवाल

दरअसल, उत्तराखंड में हरिश रावत की ओर से अलग से चुनावी गतिविधियां और यात्राएं किए जाने को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व लगातार राज्य इकाई में एकजुटता बनाए रखने पर जोर दे रहा है। हाईकमान की कोशिश है कि चुनाव से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच किसी तरह की सार्वजनिक खींचतान न दिखे और सभी नेता एक मंच पर नजर आए।



11 मिनट में 2.5 करोड़ रुपये की लूट

मेडिपल्ली: हैदराबाद के बाहरी इलाके मेडीपल्ली में टाटा ग्रुप के 'कैरेटलेन' (CaratLane) ज्वेलरी शोरूम में बड़ी चोरी हुई। बदमाशों ने स्टोर में घुसकर सिर्फ 11 मिनट में लगभग ₹2.5 करोड़ की सोने की ज्वेलरी चुरा ली। यह घटना सोमवार तड़के हुई। सोमवार सुबह 4:07 बजे, सात नकाबपोश चोरों ने मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन इलाके (मेडचल-मलकजगिरी ज़िला) में हैदराबाद-वारंगल नेशनल हाईवे पर स्थित शोरूम में संध लगाई। उन्होंने पहले बाहरी CCTV कैमरे और अलार्म सिस्टम के तार काटे और फिर लोहे की रॉड से शटर के लॉक तोड़े। इसके बाद एक व्यक्ति ने शीशा तोड़ा और अंदर घुस गया, जबकि बाकी छह बाहर पहरा देते रहे। सिर्फ पाँच मिनट के भीतर, अंदर घुसे व्यक्ति ने सोने की ज्वेलरी के 580 पीस दो बैग में भरे और स्टोर से बाहर निकल गया। सभी आरोपी सुबह 4:18 बजे मौके से भाग गए। सुबह करीब 7:00 बजे, चौकीदार ने देखा कि शटर खुला हुआ है और उसने शोरूम के फ्रैंचाइज़ी मालिक सुब्रह्मण्यम को इसकी सूचना दी। उन्होंने तुरंत

मेडीपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुँची, सबूत इकट्ठा किए और संदिग्धों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें तैनात कीं। वारदात के तरीके को देखते हुए पुलिस को शक है कि चोरी की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी। शक है कि अपराधी युवा हैं और यह अपराध बिहार के किसी गैंग का काम हो सकता है। पुलिस उन तीन कर्मचारियों की संभावित भूमिका की भी जाँच कर रही है जिन्होंने हाल ही में नौकरी छोड़ी थी। संदिग्धों की तलाश तेज़ कर दी गई है और अधिकारी CCTV फुटेज की जाँच कर रहे हैं।



सीधे किसानों के खाते में पैसे

फ्री राशन, 5 लाख का बीमा, कृषि मंत्री ने बताया पीएम मोदी के कार्यकाल में राज्य को क्या मिला

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह 25 वर्ष निरंतर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा और परिवर्तन का जरिया बनाया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ के साथ गहरा और आत्मीय रिश्ता रहा है। संगठन के दायित्वों के दौरान उन्होंने बस्तर जैसे सुदूर वनांचलों का व्यापक प्रवास किया और मुख्यमंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ के साथ विकास अनुभवों का आदान-प्रदान बनाए रखा। केंद्र सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मूल मंत्र पर काम करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।

गरीब कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में देश के लगभग 25 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली है। जनधन योजना से करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खुले, जिससे डीबीटी के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और पारदर्शिता आई। 'उज्ज्वला योजना' से छत्तीसगढ़ की 39.54 लाख महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है।



अचानक भारत क्यों आ रहे?

काठमांडू: नेपाल के गृहमंत्री सुदन गुरुंग भारत दौरे पर आ रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने सुदन गुरुंग के अगले हफ्ते भारत दौरे की पुष्टि की है। यह गृह मंत्रालय संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इस दौरान सुदन गुरुंग गृहमंत्री अमित शाह के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि गुरुंग 12 अक्टूबर को भारत के लिए रवाना होंगे और 13 अक्टूबर को बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) के गृह मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में BIMSTEC के सात सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के गृह मंत्री एक साथ आएंगे। इस समूह की स्थापना 1997 में होने के बाद से बिस्मटेक गृह मंत्रियों की बैठक पहली बार आयोजित की जा रही है। BIMSTEC देशों के गृहमंत्रियों की उद्घाटन बैठक नई दिल्ली में होगी। बैठक से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि सदस्य देशों के बीच सुरक्षा से जुड़े कई परस्पर संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि ये मुद्दे अलग-अलग तारीखों पर आयोजित बिस्मटेक गृह सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकों में सुझाए गए थे।



रंगेहाथ पकड़ा गया डीएमएचओ स्वर्णकुमारी

एल्बी नगर / हैदराबाद: ACB ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (DMHO) के ड्राइवर को ₹1 लाख की रिश्तत लेते हुए पकड़ा। रंगा रेड्डी जिले की DMHO डॉ. स्वर्णकुमारी ने LB नगर में एक फिजियोथेरेपी अस्पताल को फिर से खोलने के लिए ₹2 लाख की मांग की थी, जिसे लाइसेंस न होने के कारण बंद कर दिया गया था। पीड़ित पक्ष ने हेल्थ इंस्पेक्टर श्रीनिवास को ₹1 लाख दिए, जिन्होंने आगे यह रकम DMHO के ड्राइवर कृष्णैया को सौंप दी। ACB अधिकारियों ने ड्राइवर को कार में पैसे रखते हुए रंगे हाथों पकड़ा और मामला दर्ज किया।

किसानों की समृद्धि और कृषि विकास रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश के 25 लाख 51 हजार किसानों के खातों में 11 हजार 277 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान निधि सीधे अंतरित की जा चुकी है, जिससे उन्हें खाद, बीज और कृषि कार्यों में सीधी आर्थिक सहायता मिल रही है। सिंचाई विस्तार, आधुनिक तकनीक, फसल बीमा और किसान पंजीयन से खेती व्यवस्थित हुई है। धान उत्पादन और खरीदी में विशिष्ट पहचान रखने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री आवास ऐतिहासिक उपलब्धि

कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन औसतन लगभग 1,600 पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री ने स्वयं 3 लाख हितग्राहियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सहभागिता की। 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 3 लाख 51 हजार आवासों का गृह प्रवेश संपन्न हुआ और तीन लाख लाभार्थियों के लिए 1,200 करोड़ रुपये की किश्त जारी की गई।

जनजातीय गौरव और सर्वांगीण विकास

कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 6,691 जनजातीय गांवों में समग्र विकास का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के 56 हजार से अधिक परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' का राष्ट्रीय सम्मान दिया गया।

नक्सलवाद का खात्मा और शांति की स्थापना

उन्होंने कहा कि केंद्र की 'राष्ट्रहित सर्वोपरि' और 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ। बस्तर में 'नियद नेल्लानार' योजना से सुरक्षा केंपों के आसपास के सुदूर गांवों तक राशन, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

BIMSTEC की बैठक का एजेंडा क्या है?

बिस्मटेक के दस्तावेजों के अनुसार, मंत्रिस्तरीय बैठक को गृह/आंतरिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का समर्थन प्राप्त होगा। सुरक्षा सहयोग बिस्मटेक के क्षेत्रीय एजेंडों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिस्मटेक शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने कानून प्रवर्तन, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

आतंकवाद पर BIMSTEC में होगी बाद

नेताओं ने आतंकवाद विरोधी और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए बिस्मटेक के गृह मंत्रियों की बैठकें आयोजित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठकें जारी रखने का भी निर्णय लिया। नेपाली अधिकारियों के अनुसार, मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले बिस्मटेक के गृह सचिवों की बैठक होगी।

अमित शाह से मिलेंगे सुदन गुरुंग

नेपाली अधिकारियों के अनुसार, सुदन गुरुंग के इस आयोजन के दौरान अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। सुदन गुरुंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी अलग से बैठक करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बिस्मटेक के सदस्य देश सुरक्षा मामलों पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सदस्य देशों के वरिष्ठ सुरक्षा और गृह अधिकारियों के बीच हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

